

जगदीश व अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

सितंबर 18, 2007

[एस. बी. सिन्हा और एच. एस. बेदी, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा. 302 सपठित धारा 34

हत्या-हथियारों से लैस चार अभियुक्त व्यक्तियों ने कथित रूप से मृतक पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई-विचारण अदालत ने उन सभी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया-उच्च न्यायालय द्वारा पलट दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय, बरी किए जाने के फैसले पर विचार करते हुए, हालांकि जो सामग्री अभिलेख पर लाई गई है, उसका पुर्नमूल्यांकन कर सकता है किन्तु जब दो विचार संभव हो तो सामान्य अनुक्रम में दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल तभी अनुमत है जब रिकॉर्ड पर सामग्री केवल एक निष्कर्ष पर ले जाएगी कि अपीलकर्ता दोषी है और इसे निचली अदालत के तर्क को पूरा करने की

आवश्यकता है-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि निचली अदालत का दृष्टिकोण नकारात्मक था क्योंकि इसमें केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों पर चर्चा की गई थी- उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह का दृष्टिकोण रखने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था-उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन।

शिकायतकर्ता, पी.डब्लू. 1 ने आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वह अपने भतीजों के साथ एक 'जी' के घर ईंटें ले जाने के लिए बैलगाड़ी उधार लेने के लिए गया था, उन्होंने उन्हें एक 'बी' के 'बेडा' से लेने के लिए कहा और अपने बेटे को उक्त स्थान तक उनके साथ जाने के लिए कहा। जब वे मौके पर पहुंचे तो हथियारों से लैस आरोपी उनके घरों से बाहर आए और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता, उसके भतीजे और दूसरे को देखकर, अभियुक्तों में से एक ने कथित तौर पर अपने भतीजे, मृतक की गर्दन पर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा घाव हो गया। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने भी उसकी पीठ और गर्दन पर चोटें लगाईं। मृतक को चोट पहुंचाने के बाद आरोपी भाग गया। पीड़ित ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जाँच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दायर

किया। चिकित्सीय साक्ष्य बनाम नेत्र संबंधी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने राय दी कि तीन अभियुक्तगण की भागीदारी संदिग्ध थी और पी.डब्ल्यू.-2 की साक्ष्य में विरोधाभास पाया कि न्यायालय में अभियोजन साक्ष्यगण द्वारा दिये गये विरोधाभासी कथन बनाम अभियोजन कहानी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में खुलासा कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को क्षति कारित की गई थी, यह संदिग्ध था तथा घटना की कडिया जिसमें हमला कारित किया गया था, वह भी संदेहपूर्ण था, जो विरोधाभासी व असंगत था। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया। राज्य द्वारा अपील पेश किये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई इसलिए यह अपील पेश की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. उच्च न्यायालय दोषमुक्ती के फैसले की अपील पर विचार करते हुए विचारण न्यायाधीश के तर्क को जानना आवश्यक है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय बरी करने के फैसले पर विचार कर रहा था, पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की फिर से पुनर्मुल्यांकन करने के लिए खुला था, लेकिन यह कानूनी सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां दो विचार संभव हैं, उच्च न्यायालय सामान्य रूप से बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

रतन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (2007) 5 स्केल 472, आश्रित पर।

1.2. इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानूनी अनुज्ञेय है बशर्त अभिलेखों पर सामग्री केवल एक निष्कर्ष पर ले जाए कि अपीलार्थी दोषी हैं। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को भी लगभग पुनः प्रस्तुत किया था साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करता है। यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि निचली अदालत का दृष्टिकोण नकारात्मक था। उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में केवल विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक अलग दृष्टिकोण क्यों लिया जाना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आगे बढ़े कि चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू-1) और अन्य गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हैं। इस आधार पर अभियोजन प्रकरण को फेंका नहीं जा सकता।

1.3. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए अपने लिए सही सवाल नहीं उठाया। यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा

किए गए निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने का इरादा रखता है, तो रिकॉर्ड पर सामग्री का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना उसकी ओर से अनिवार्य था। उच्च न्यायालय को भी विचारण न्यायाधीश के तर्क को पूरा करना आवश्यक था। यदि विचारण न्यायाधीश साक्ष्य के मूल्यांकन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट घटना का समय सही नहीं था, जबकि कहा जाता है कि घटना सुबह 8.00 बजे हुई थी, लेकिन वास्तव में यह उससे बहुत पहले हुई थी, तो यह राय नहीं दी जा सकती कि प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य के एक घंटे के भीतर दर्ज की गई थी। अभियुक्तों में से एक और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयान का उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए था कि निचली अदालत द्वारा इस तरह की कवायद का सहारा लिया गया था। उच्च न्यायालय ने भी एक गंभीर अवैधता की है अनुमान लगाया कि चिकित्सा साक्ष्य ने नेत्र साक्ष्य की पुष्टि की। जाहिर है कि ऐसा नहीं था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

[पैरा 14 और 15] [1088-सी-एफ]

राजस्थान राज्य बनाम भंवर सिंह, [2004] 13 एससीसी 147; कल्लू उर्फ मसीह व अन्य बनाम एम. पी. राज्य, [2006] 10 एससीसी 313 और

रामप्पा हलप्पा पुजारी व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 6
स्केल 206, पर निर्भर था।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील संख्या 988/2006

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच ग्वालियर की आपराधिक
अपील संख्या 23 का 1991 के निर्णय व आदेश से

डॉ. टी. एन. सिंह, लखन सिंह चौहान और डॉ. कैलाश चंद
याचिकाकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया था

1. इनमें दो अपीलकर्ताओं ने याचिका दायर की है, यह अपील मध्य
प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, ग्वालियर पीठ द्वारा ग्वालियर में पारित
दिनांक 23.03.2006, जिसके तहत 1987 की धारा संख्या 38 में विद्वान
सत्र न्यायाधीश, दतिया द्वारा पारित दिनांक 30.04.1990 के बरी होने के
फैसले को उन्हें आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पठनीय धारा 302 के
तहत दंडनीय अपराध के कथित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए और
उन्हें आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई
थी से व्यथित होकर पेश की थी।

2. मंगल सिंह (पी.डब्लू.-1) नामक व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट
दर्ज कराई थी। यह आरोप लगाते हुए कि वह अपने भतीजे गब्बर सिंह
और एक अन्य भतीजे मानसिंह (मृतक) के साथ सुबह लगभग 8 बजे ईट

ले जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी उधार लेने के लिए गोविंदस कुर्मी के घर गया था। उन्हें बताया गया कि यह बिरजू के 'बेडा'में है। उन्होंने अपने बेटे को उक्त स्थान तक उनके साथ जाने के लिए कहा। जब गाड़ी का नेतृत्व किया जा रहा था और वे मांगों कुर्मी के घर के पास पहुंचने पर उन्होंने उसे बल्लम से लैस, ठाकुरदास को कुल्हाड़ी से लैस, जगदीश को कुल्हाड़ी से लैस और देवीदयाळ को फरसा से लैस, अपने घर के चबूतरे पर खड़ा पाया। उन चारों को उन्हें यह कहते हुए गाली देना शुरू कर दिया कि वे आखिरकार उस दिन मृतक को खत्म कर देंगे। ठाकुरदास ने कथित तौर पर मृतक मानसिंह की गर्दन पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया। उसने कथित तौर पर अपनी गर्दन पर एक और वार किया जिससे उसे एक बड़ा घाव हो गया। जगदीश ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया। देवीदयाळ ने मृतक की गर्दन पर एक फारसा प्रहार किया और मांगो ने उसकी पीठ पर एक बल्लम प्रहार किया। उन्होंने मृतक की पीठ पर दो या तीन और वार किए, जिसके बाद वे भाग गए।

3. इस प्रकार, ठाकुरदास और मांगो के साथ अपीलकर्ताओं पर मानसिंह की हत्या का मुकदमा चलाया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में अन्य बातों के साथ-साथ मंगल सिंह (मुखबिर) से पीडब्लू-1, कैलाश और डब्बू, जिन्हें चश्मदीद गवाह कहा जाता है, से क्रमशः पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के रूप में परिक्षण किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों पर अविश्वास किया। मामले में अपीलार्थियों का बचाव यह था कि मृतक मानसिंह अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था। उनके कई दुश्मन थे। उनके एक व्यक्ति प्रागी चौधरी के साथ भी तनावपूर्ण सम्बन्ध थे। उन्होंने प्रागी की लकड़ी ले ली थी और लाल सिंह की जमीन हड़प ली थी। उन्होंने भागीरथ पर भी गोली चलाई थी और लल्लू पर हमला किया और चोरी कर ली इसलिए, हो सकता है कि उनकी हत्या उनमें से किसी ने की हो।

5. अपीलार्थी ने डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में एक बृजनंदन की जाँच की। उसके कथन के अनुसार घटना के दिन सुबह लगभग 4 और 5 बजे गवाह जब सुबह आराम करने जा रहा था, तो उसने कुए के पास मानसिंह का शव पड़ा देखा। ठाकुरदास उनके साथ था। इस बीच कैलाश भी पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने ठाकुरदास से मृतक के भाई मंगल सिंह को फोन करने को कहा। उनके अनुसार, मंगल सिंह ने कहा था कि मृतक के कई लोगों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे और हो सकता है कि उनमें से किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। बाद में पुलिस वहां पहुंची और उससे पूछताछ की।

6. विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष, डॉ. आर. एन. गुप्ता, जिन्होंने शव का परीक्षण किया खुद को पीडब्लू-3 के रूप में परीक्षित करवाया। उनके अनुसार, मृत शरीर के पोस्टमार्टम पर उन्हें निम्नलिखित बाहरी चोटें मिलीं:

"1. गर्दन के दाहिनी तरफ कटा हुआ तिरछा घाव आकार 3 x 1/2"

2. एक और कटा हुआ तिरछा घाव 1" उपरोक्त घाव के ऊपर 2.5 x 1/2"

3. घाव, गर्दन पर पीछे की ओर आकार 3.5 एक्स-रे 1"

4. घाव, आकार 3 x 1/2" यह. गर्दन का हिस्सा।

5. घाव, 3 x 1" गर्दन के बाईं तरफ।

गर्दन पर सभी घाव काफी गहरे थे जिसके कारण श्वसन नलिका, अन्नप्रणाली खाद्य नलिका, रक्त वाहिकाएँ और हड्डियाँ काट दिए गए। घाव के चारों ओर खून जमा हुआ था, और किनारे थे।

6. 3 x 1" आकार का कटा हुआ घाव दोनों कंधों के बीच में एक गर्दन के पीछे (गवाह संख्या 3 की मूल प्रति पढ़ने योग्य नहीं है)

7. बांये कंधे पर एक कटा हुआ घाव। कंधे 2 x 1/2"। चेहरा पीला पड़ गया, खून के धब्बों के कारण आंखें बंद थी। मुँह थोड़ा खुला था।"

7. उक्त पोस्टमॉर्टम जाँच 27.6.1987 पर आयोजित की गई थी। डॉक्टर के अनुसार, मानसिंह की पीठ पर कोई चोट नहीं थी और सभी सातों चोटें केवल एक हथियार से कारित की जा सकती हैं जबकि दो कुल्हाड़ी और एक फरसा, जिन्हें अपराध का हथियार कहा जाता था, उनके सामने पेश किया गया, तो उन्होंने कहा कि चोटों के आकार को देखते हुए, यह कुल्हाड़ी से हो सकता था, लेकिन फरसा से नहीं हो सकता था।

8. यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त बिरजू निश्चित रूप से एक गवाह था जिसका नाम आरोप पत्र में दिखाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उससे पूछताछ नहीं की।

9. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दो गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य का समर्थन नहीं करते हैं। यह पाया गया कि देवीदयाळ ने कथित तौर पर फारसा का प्रहार किया था और जगदीश पर मानसिंह की पीठ पर प्रहार करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन मृतक की पीठ पर कोई चोट नहीं मिली थी और न ही उसकी पीठ पर कोई कुल्हाड़ी या बल्लम की चोट पाई गई थी। मृतक पर बल्लम या लाठी का घुसा हुआ घाव नहीं था। इसलिए, उनकी राय थी कि मांगो, जगदीश और देवीदयाळ की भागीदारी संदिग्ध थी। आगे यह राय दी गई कि जगदीश पर आरोप लगाया गया था कि उसने मृतक की पीठ पर दो-तीन फरसा से वार किए थे, जबकि देवीदयाळ ने उसकी पीठ पर दो-तीन कुल्हाड़ी से वार किए थे और जगदीश के बारे में कहा गया था कि उसने दो-तीन लुहांगी से वार किए थे लेकिन यह सबूत भी चिकित्सा साक्ष्यों से गलत साबित हुआ।

10. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी पाया कि पीडब्लू-2 ने खुद का खंडन किया जहाँ तक उन्होंने कहा कि घटना के समय वह अपने कुएं पर थे, जो मांगो कुर्मी के घर से लगभग 8 से 10 फरलांग दूर है। उनके अनुसार बिस्तर से उठने के बाद वह सीधे अपने कुएं में जाते थे।

उन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया था कि वे सुबह लगभग 4 और 5 बजे अपने कुएं पर आए थे और उस समय उन्हें मानसिंह का शव वहां पड़ा मिला था। उक्त तथ्य को डब्लू (पीडब्लू-4) के बयान से समर्थन मिलता है और बचाव की कहानी द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था, जैसा कि बृजनंदन (डीडब्ल्यू-1) द्वारा खुलासा किया गया था।

11. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाह पक्षद्रोही घोषित नहीं किए गए थे। जबकि बयान के एक स्थान पर, पीडब्लू-4 ने कहा कि वह मृतक पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले का गवाह रहा है, उसकी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने शव वहाँ पड़ा पाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा यह भी पाया गया था कि मृतक की पीठ पर कुल्हाड़ी या बल्लम से कोई चोट नहीं पाई गई थी। अभियोजन गवाहों के अनुसार, आरोपी मंगल सिंह, जगदीश और देवीदयाळ ने उसकी पीठ पर बल्लम, लाठी या कुल्हाड़ी से वार किया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष की कहानी के बारे में, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है, यह संदेहपूर्ण था कि क्या अपीलकर्ताओं ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी। यह भी पाया गया था कि जिस घटना के क्रम में हमले किए गए थे, वह भी विरोधाभासी और असंगत होने पर संदेह था।

12. उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले की अपील पर विचार करते हुए, इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायाधीश के उपरोक्त तर्कों को पूरा करने के लिए दोषमुक्ति की आवश्यकता थी। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय बरी करने के फैसले पर विचार कर रहा था, पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की फिर से सराहना करने के लिए खुला था, लेकिन यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां दो विचार संभव हैं, उच्च न्यायालय सामान्य रूप से बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। [रतन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य देखें, (2007) 5 स्केल 472]।

13. इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानून में अनुज्ञेय है बशर्ते कि अभिलेखों पर सामग्री केवल एक निष्कर्ष पर ले जाए कि अपीलार्थी दोषी हैं। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को भी लगभग पुनः प्रस्तुत किया था। इसने स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया। यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि निचली अदालत का दृष्टिकोण नकारात्मक था। उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में केवल विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक अलग दृष्टिकोण क्यों लिया जाना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च

न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि प्रत्यक्षदर्शी मंगल सिंह (पीडब्लू-1) और अन्य गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष की कहानी, अभियोजन मामले की पुष्टि करते हैं। अभियोजन केस फेंका नहीं जा सकता।

14. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए अपने लिए सही सवाल नहीं उठाया। यदि उसका इरादा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने का था, तो उसकी ओर से अभिलेख पर सामग्री का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना अनिवार्य था। उच्च न्यायालय को विद्वान विचारण न्यायाधीश के तर्क को पूरा करने की भी आवश्यकता थी। यदि विद्वान विचारण न्यायाधीश साक्ष्य की विवेचना करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट घटना का समय सही नहीं था, जबकि कहा जाता है कि घटना सुबह 8 बजे हुई थी, लेकिन वास्तव में यह उससे बहुत पहले हुई थी, यह राय नहीं दी जा सकती थी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के एक घंटे के भीतर दर्ज की गई थी। मंगल सिंह और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान का उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए था कि इस तरह की कवायद का सहारा विद्वान सत्र न्यायाधीश ने लिया था। उच्च न्यायालय ने भी एक गंभीर अवैधता की क्योंकि यह अनुमान लगाया कि चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। जाहिर है कि ऐसा नहीं था।

15. इसलिए, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय को विचारण न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

16. राजस्थान राज्य बनाम भंवर सिंह, [2004] 13 एस.सी.सी.

147, में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

"6. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है हालाँकि, व्यक्तिगत रूप से कुछ परिस्थितियाँ अभियोजन प्रकरण की सच्चाई को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। पी.डब्ल्यू. 5 विधवा जिसने इन लोगो को अपने पति के शव को खोजने भेजा के स्पष्ट कथन से पी.डब्ल्यू. 3, 4, था 8 की घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध बना देती है। उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से देखी गई दुर्बलताएँ यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित नहीं हुआ है। यह काफी अस्वाभाविक है कि पीडब्लू 3, 4 और 8 हमले के गवाह होने के बावजूद गवाही देने के बाद चुप रहे। उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतक पर हमले के बाद उन्होंने क्या किया? इसके अलावा प्राथमिकी दर्ज करने में एक दिन से अधिक की अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन पक्ष के संस्करण की सच्चाई पर गंभीर

संदेह पैदा करता है। केवल एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती है। लेकिन उस पर वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ, निश्चित रूप से, यह एक कारक है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को कम करता है। अंत में चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य के साथ पूरी तरह से भिन्न थे। यद्यपि नेत्र संबंधी साक्ष्य को चिकित्सा से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, जहाँ चिकित्सा साक्ष्य नेत्र को पूरी तरह से असंभव बनाता है जो अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक माना जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है। बरी किए जाने के खिलाफ अपील होने के कारण, हम इस पर विचार नहीं करते हैं एक उपयुक्त मामला होना जहाँ किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। याचिका विफल रही और खारिज कर दिया जाता है।"

17. फिर से कल्लू उर्फ मसीह व अन्य बनाम एम. पी. राज्य, [2006] 10 एससीसी 313, इस न्यायालय ने राय दी:

"8. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय, अपीलीय न्यायालय की शक्ति से कम नहीं है। जहाँ दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में शक्तिया काम में ली गई व

दोनों प्रकार की अपीलों में शक्तिया निहित है। पूरे साक्ष्य की समीक्षा करना। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बरी करने के आदेश में अपीलीय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जहाँ विचारण न्यायालय का निर्णय साक्ष्य पर आधारित होता है और लिया गया दृष्टिकोण उचित और प्रशंसनीय है। विचारण न्यायालय का निर्णय केवल इसलिए कि एक अलग दृष्टिकोण संभव है उल्टा नहीं जायेगा अपीलीय न्यायालय के दिमाग में यह भी होना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की अवधारणा है और अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। आगे अगर हस्तक्षेप करने का निश्चय किया जाता है तो विचारण न्यायालय के निर्णय से भिन्न कारण दिया जाना चाहिए।"

[यह भी देखे रतनलाल (पूर्व) और रामप्पा हल्लपा पुजारी व अन्य बनाम कर्नाटका राज्य (2007)6 स्केल 206]

18. उपरोक्त अंकित कारणों से उच्च न्यायालय का निर्णय स्थिर नहीं रखा जा सकता, जो अपास्त किया जाता है, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण की अन्य प्रकरण के संबंध में आवश्यकता नहीं हो तो बाद में रिहा कर दिये जावे।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।